



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 108]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 26, 1981/चैत्र 5, 1903

No. 108]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 26, 1981/CHAITRA 5, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1981

सं० का० नि० 212 (अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित
आदेश सर्वसाधारण को जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

"सं० आ० 115

संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 1981

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का
प्रयोग करते हुए, वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के
पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात्:—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) आदेश,
1981 है।

2. साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस
आदेश के निर्वाचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह
किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वाचन के लिए लागू होता है।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खण्ड (1) के उपबन्धों के अनुसार—

(क) नीचे सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के
राजस्व के महायुता अनुदान के रूप में, उक्त सारणी के स्तम्भ (2) से
(6) में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट राशियाँ उन स्तम्भों में वणित

सेक्टरों और सेवाओं के प्रशासन संबंधी स्तर को ऊँचा उठाने के लिए
ऐसे कार्यक्रमों पर 1 अप्रैल, 1980 से प्रारम्भ होने वाले वित्तीय
वर्ष में, भारत की संचित निधि पर भारित होंगी जो राजस्व और पूँजी
प्रकृति के व्यय के लिए हैं:—

सारणी

राज्य निम्नलिखित से संबंधित स्तर को ऊँचा उठाने के लिए

व्यायिक प्रशासन	पुलिस प्रशासन	जेल प्रशासन	राजस्व जिला और जनजाति प्रशासन	स्टाम्प, रजिस्ट्री- करण और खजाना प्रशासन
--------------------	------------------	----------------	--	---

(लाख रुपयों में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गोअ्र प्रदेश	20.00	338.00	57.21	171.00	..
असम	6.19	412.35	..	193.55	..
बिहार	..	496.24	62.93	185.00	..
हिमाचल प्रदेश	1.40	65.92	..	19.66	..
जम्मू-कश्मीर	..	133.21	11.00
केरल	0.56	7.45	..

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मध्य प्रदेश	8 18	467.94	139.28	377.50	—6.00
मणिपुर	10.50	113.53	25.17	100.00	..
मेघालय	..	17.50	12.20	28.50	..
मागालैण्ड	27.00	50.00	..	12.80	..
उड़ीसा	2.00	148.10	104.97	175.07	..
राजस्थान	20.00	258.35	8.00	79.25	12.00
सिक्किम	7.00	—	..
तमिलनाडु	1.00	373.38	340.00	3.28	..
त्रिपुरा	25.85	33.07	..	13.50	2.00
उत्तर प्रदेश	163.84	1749.73	304.48	405.45	195 79
पश्चिमी बंगाल	110.05	250.08	..	29.50	..

परन्तु ऊपर विनिर्दिष्ट राशियाँ, ऊपर विनिर्दिष्ट और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सेक्टरों और सेवाओं के प्रशासन संबंधी स्तर को ऊँचा उठाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कार्यक्रमों पर खर्च की जाएंगी :

परन्तु यह और कि यदि किसी प्रशासन से संबंधित कार्यक्रम या कार्यक्रमों पर वास्तविक व्यय, जैसा कि उक्त वर्ष के लेखाधो में प्रकट होता है, उक्त प्रशासन के मामले ऊपर विनिर्दिष्ट अनुदान की रकम से कम है तो इस प्रकार अधिक संवत् रकम ऐसी राशि या राशियों के विषय समायोजित की जाएंगी जो उसी प्रयोजन या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी पश्चात्कर्ती वर्ष में उस राज्य को संदेय हो जाए ।

(ख) इस संबंध में वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, नीचे सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के राजस्व के सहायता अनुदान के रूप में 1 अप्रैल, 1979 को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में, उस प्रत्येक राज्य द्वारा नए उधार लेने और उधार देने के कारण शुद्ध ब्याज बाधित्व के मद्दे, सारणी के स्तम्भ (2) में उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियाँ हैं :—

सारणी					
राज्य	(लाख रुपयों में)				
हिमाचल प्रदेश	5.48
मणिपुर	40.93
मेघालय	5.28
मागालैण्ड	10.95
उड़ीसा	27.37
सिक्किम	1.64
त्रिपुरा	7.15

परन्तु यदि उस वर्ष के खातों में प्रकट किए गए वास्तविक उधार लेने और उधार देने के धंक या उधार लेने पर ब्याज की बरें, ऊपर विनिर्दिष्ट अनुदानों के भवधारण करने में हिसाब में लिए गए सुसंगत धंकों से भिन्न हैं, तो इस प्रकार संवत् अनुदान की रकम किसी ऐसी राशि या राशियों के प्रति, जो उसी या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी भी पश्चात्कर्ती वर्ष में उस राज्य को संदेय हो जाए, समायोजित की जाएगी ।

(2) 1 अप्रैल, 1980 से प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में उप-पैरा (1) के खण्ड (क) और (ख) के अधीन किसी राज्य को संदेय कोई राशि या राशियाँ उस राशि या राशियों के प्रतिरिक्त होगी या

होगी जो संविधान (राजस्व वितरण) अधेश, 1979 के पैरा 4 के उप-पैरा (1) के अनुसरण में उक्त वित्तीय वर्ष में उस राज्य को संदेय हो ।

नीलम सजीव रेड्डी, राष्ट्रपति ।"

[सं० फा० 19 (1)/81-एम-1]

६० बेंकट सूर्य पेरिशाल्त्री, मन्त्रि

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 1981.

G.S.R. 212(E).—The following Order made by the President is published for general information:—

"C.O. 115

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) ORDER, 1981

In exercise of the powers conferred by article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Finance Commission, hereby makes the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 1981.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 1980, as grants-in-aid of the revenues of:—

(a) each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in each of the columns (2) to (6) of the said Table, towards expenditure, of revenue and capital nature, on programmes for upgradation of standards relating to the administration of the sectors and services mentioned in those columns:—

TABLE

For upgradation of standards relating to					
State	Judicial adminis-	Police adminis-	Jail adminis-	Revenue, District and Tribal adminis-	Stamps, Registration and Treasuries
	tration	tration	tration	and	admi-
(Rs. in lakhs)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Andhra Pradesh	20.00	338.00	57.21	171.00	..
Assam	6.19	412.35	..	193.55	..
Bihar	..	496.24	62.93	185.00	..
Himachal Pradesh	1.40	65.92	..	19.66	..

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jammu and Kashmir	..	133.21	11.00
Kerala	0.56	7.45	..
Madhya Pradesh	8.18	467.94	139.28	377.50	6.00
Manipur	10.50	113.53	25.17	100.00	..
Meghalaya	..	17.50	12.20	28.50	..
Nagaland	27.00	50.00	..	12.80	..
Orissa	2.00	148.10	104.97	175.07	..
Rajasthan	20.00	258.35	8.00	89.25	12.00
Sikkim	7.00
Tamil Nadu	1.00	373.38	340.00	3.28	..
Tripura	25.85	33.07	..	13.50	2.00
Uttar Pradesh	163.84	1749.73	304.48	405.45	105.79
West Bengal	110.05	250.08	..	29.50	..

Provided that the sums specified above shall be expended on programmes formulated by the State Governments for upgrading the standards relating to the administration of the sectors and services specified above and approved by the Central Government;

Provided further that if the actual expenditure on approved programme or programmes relating to any administration, as revealed in the accounts of that year, is lower than the amount of grant specified above against that administration, the amount so paid in excess shall be adjusted against any sum or sums which may become payable to that State in any of the succeeding years for the same purpose or any other purpose;

- (b) each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in column (2) of the Table, towards net interest liability on account of fresh borrowings and lendings of each of those States, in the financial year commencing on the 1st day of

April, 1979, as per the recommendations of the Finance Commission in this regard:—

TABLE

State	(Rs. in lakhs)
(1)	(2)
Himachal Pradesh	5.48
Manipur	40.93
Meghalaya	5.28
Nagaland	10.95
Orissa	27.37
Sikkim	1.64
Tripura	7.15

Provided that if the figures of actual borrowings and lendings as revealed in the accounts of that year, or the rates of interest on borrowings are different from the relevant figures taken into account in determining the grants specified above, the amount of grant so paid shall be adjusted against any sum or sums which may become payable to that State in any of the succeeding years for the same purpose or any other purpose.

- (2) Any sum or sums payable under clauses (a) and (b) of sub-paragraph (1) to any State, in the financial year commencing on the 1st day of April, 1980 shall be in addition to the sum or sums payable to that State in that financial year in pursuance of sub-paragraph (1) of paragraph 4 of the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 1979.

N. SANJIVA REDDY,
President."

[No. F. 19(1)/81-L.I.]
R.V.S. PERISASTRI, Secy

